ISSN: 2319-7943 IMPACT FACTOR : 5.4906 (UIF) VOLUME - 5 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2017

TACTFUL MANAGEMENT RESEARCH JOURNAL

श्रमिकों के अधिकारों के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षण एवं अभिवृत्ति

डॉ. शिरीष पाल सिंह
सह प्रोफेसर , महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय , (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)वर्धा (महाराष्ट्र)

प्रस्तावना :

उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, प्रबंध, श्रम तथा साहस माने जाते हैं। इनमें अन्य कारण इतने महत्वपूर्ण नहीं जितना कि श्रम। मार्क्स तो श्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। असल में प्रबंधक और श्रमिक दोनों ही श्रमिकों के अन्तर्गत आते हैं इन्हें मानसिक श्रम तथा शारीरिक श्रम में भले ही विभाजित किया जाता रहे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण किया जाता रहा है। भारतीय समाजवाद वर्गउ संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग की भावना से अनुप्राणित है। समाजवाद सर्ववर्गों के कल्याण की बात करता है। साम्यवाद केवल श्रमिक वर्ग के कल्याण की बात करता है। भारतीय समाजवाद में अन्य वर्गों के साथ श्रमिकों के कल्याण के लिए भी प्रयासरत रहता है।

हमारा संविधान जहां उद्देशिका में आर्थिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है वहीं मूलाधिकारों में समता, दूसरों के अधिकारों की रक्षा, सम्मान, प्राकृतिक न्याय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था, बालश्रम तथा बलातश्रम का विरोध करता है। हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्वों में काम की न्यायसंगत दशाओं, कर्मकारों का प्रबंधन में योगदान, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी लागू करने को अपना नीति निदेशक तत्व मानता है।

बलात्श्रम को रोकने के लिए कानूनों का निर्माण, अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक (नियोजन तथा सेवा परिस्थितियों का विनियमन) अधिनियम–1979, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005, समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1976, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम–1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948, वेतन भुगतान अधिनियम–1936, बोनस भुगतान अधिनियम–1965, वी.वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा, स्वायत्तशासी संस्था की स्थापना, श्रमिक मुआवजा अधिनियम–1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम–1926, श्रमिक मुआवजा अधिनियम–1923, प्रसूति लाभ अधिनियम–1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम–1972, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, जमा राशि से जुड़ी कर्मचारी बीमा योजना–1976, आदि अधिनियम कर्मचारियों के हितों के हेतु बनाए गए है।

हमारे अनुसंधान में श्रमिकों के अधिकारों के लिए तीन कथन प्रत्यक्षण तथा तीन कथन अभिवृत्ति से संबंधित सम्मिलित है। इन कथनों पर अध्यापकों के अभिमतों को सारणी तथा आलेख 1 (क) तथा सारणी तथा आलेख 1 (ख) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1 (क)
श्रमिकों के अधिकारों के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षण

कथन	प्रकार	अभिमत श्रेणियां		अंक	श्रेणी क्रम
		सहमत	असहमत		
18	विपक्ष	249	251	751	3
39	पक्ष	477	23	977	1
56	विपक्ष	186	314	814	2

कथन

18 न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना गलत है क्योंकि वेतन का निर्धारण तो मांग और पूर्ति के आधार पर अपने आप ही होता है।
39. अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों को अपने संघ बनाने को अधिकार होना चाहिए।
56. बंधुआ मजदूरी एक छलावा है। पहले तो व्यक्ति काम पाने के लिए शर्तों पर तैयार हो जाता है फिर सरकार को शिकायत करता है।

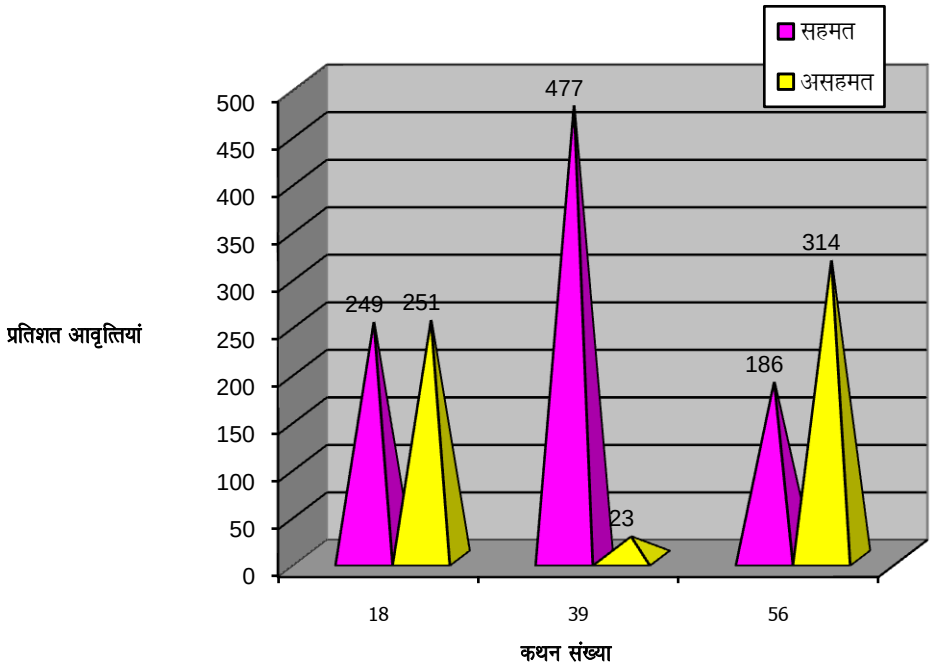

आलेख 1 (क)
श्रमिकों के अधिकारों के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षणः कथनों पर अभिमत

निर्वचन :

1. संघ बनाने का समर्थन 95.4 प्रतिशत अध्यापक कर रहे है।
   बंधुआ मजदूर को छलावा केवल 37.2 प्रतिशत मान रहे है जबकि विपक्ष के इस कथन पर असहमत अध्यापकों की प्रतिशत 62.8 है।
2. न्यूनतम वेतन का निर्धारण मांगपूर्ति सिद्धांत के पक्षधर 50.2 प्रतिशत अध्यापक हैं जबकि 49.8 प्रतिशत अध्यापक न्यूनतम वेतन का निर्धारण उचित नहीं मान रहे है।

सारणी 1 (ख)
श्रमिकों के अधिकारों पर अध्यापकों की अभिवृत्ति

क0सं0	प्रकार	अभिमत श्रेणियां					अंक	श्रेणी क्रम
		पूर्ण सहमत	आंशिक सहमत	अनिश्चित	आंशिक असहमत	पूर्ण असहमत		
25	पक्ष	341	77	19	21	42	2154	2
26	पक्ष	356	85	21	9	29	2230	1
42	विपक्ष	76	141	80	85	118	1528	3

कथन :

25. न्यूनतम मजदूरी से कम पर मजदूरों से काम लेना बेगार है।
26. भूख गरीबी तथा कंगाली के कारण लोगों को बेगार करनी पड़ती है।
42. ट्रेड यूनियनों तथा संघों को प्रतिबंधित किया जाए क्योंकि ये उत्पादन कार्यों में व्यवधान डालते है।

निर्वचन :

श्रमिक अधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति अंकों का विश्लेषण इस प्रकार है :

1. अतिउच्च बहुमत से अध्यापक मानते हैं कि बेगार का कारण भूख तथा गरीबी है।
2. न्यूनतम मजदूरी के कम मजदूरी देने को अध्यापकों में से 83.6 प्रतिशत अध्यापक बेगार मानते हैं जबकि 12.6 प्रतिशत ऐसा नहीं मानते शेष अनिश्चित है।
3. ट्रेड यूनियनों को प्रतिबंधित करने का विरोध 118+82 = 200 अध्यापक कर रहे हैं जबकि 141+76 =217 अध्यापक समर्थन कर रहे हैं। 80 अध्यापक इस संदर्भ में अनिश्चित है। इस प्रकार केवल 17 मतों अर्थात 3.4 प्रतिशत मतों से ट्रेड यूनियनों को प्रतिबंधित करना चाहते है।

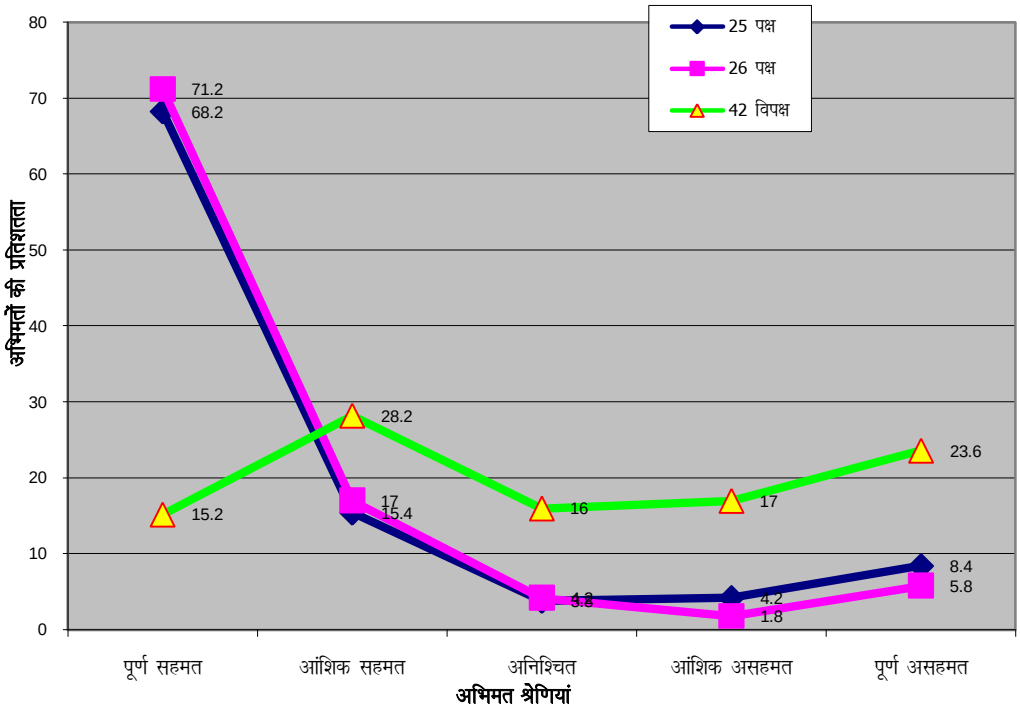

आलेख 1 (ख)
श्रमिकों के अधिकारों पर अध्यापकों की अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों पर अभिमत श्रेणियों पर अभिमत

निहितार्थ :

अध्यापकों का मानना है कि अपने हितों के संरक्षण के लिए अपने संघ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। बंधुआ मजदूरों के हित का समर्थन अध्यापक उच्च प्रतिशत में कर रहे है। अध्यापक बेगार का कारण भूख, गरीबी और कंगाली को मानते है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने के संबंध में अध्यापकों की राय न तो पक्ष में है और न ही विपक्ष में है। जबकि ट्रेड यूनियनों के संबंध भी अध्यापकों की राय स्पष्ट नहीं है।वे अल्प मतों से ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाने के पक्षधर है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

Govt. of India:

: Report of committee on Emotional Intigration, Ministry of education, 1962.

: Report of the committee for review of National policy of education 1986, 1990.

: Report of the committee on Religious and Moral. Instruction. Ministry of Education. 1959.

: Report of the education commission on education and National Development 1964-66. Ministry of seducation. 1966.

: Report of the National Policy on education (1986) Ministry of Human Resources.

: भारत का संविधान : विधि एवं न्याय मंत्रालय विधाई विभाग, राजभाषा खण्ड 1996

: भारत 2007, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय,

: भारत 2008 प्रकाशन विभाग, सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय

: कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2006, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानवाधिकार विकास विशेषांक।

: बालक अधिनियम 1960 (1 अगस्त 1985 तक यथा विद्यमान, विधि एवं न्याय मंत्रालय)

: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1 फरवरी 1999 तक यथाविद्य)

: The Protection of Human Right Act 1993.

: बाल अधिकार और बाल संरक्षण, आशारानी बोहरा, प्रकाशन विभाग (1999)।

: बाल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, रेणुका चौधरी योजना नवम्बर 2008.

: भारतीय बच्चे : एक विवरण, योजना, नवम्बर 2006

: गरीबों की शिक्षा के हक के लिए संघर्ष, शांता सिन्हा, योजना, नवम्बर 2006

: ग्रामीण बच्चों के लिए कठिन दौर, कृष्ण कुमार, योजना, नवम्बर 2006

: बाल कल्याण के लिये अधिकारोन्मुख राह अपनाएं, योजना, नवम्बर 2007

: 46 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण से ग्रस्त, योजना, नवम्बर 2007

: ग्रामीण बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007

: बालश्रम एक कलंक, कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007

: संकट में बचपन, कुरुक्षेत्र 2007

: बालश्रम समस्या कारण एवं प्रभाव, कुरुक्षेत्र 2007

: ग्रामीण भारत में बालश्रम, कुरुक्षेत्र 2007

: Challenges of Education: Policy Perspectives, New Delhi, 1985.

: Report of the Working Group to Review Teachers Training Programme (in the Light of the Need for Value Orientation), 1983.

Singh, Bhopal : जनसंख्या शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन, गढ़वाल वि.वि. की पीएच.डी. का शोध प्रबन्ध अप्रकाशित (1985)

: जनसंख्या शिक्षा, मेरठ लायल बुक डिपो (2006)
: पर्यावरण शिक्षा, मेरठ लायल बुक डिपो (2007)
: पर्यावरण अध्ययन, मेरठ लायल बुक डिपो (2008)

UNO :

: जातीय भेदभाव का उन्मूलन सम्बन्धी घोषणा पत्र 20 नवम्बर 1963.
: मानवाधिकारों का घोषणा पत्र।
: बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र दिनांक 20 नवम्बर 1989
: संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों की समाप्ति सम्बन्धी अभिसमय, 3 दिसम्बर 1981
: सिविल तथा राजनीतिक अधिकार : अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा।